लोक सभा सचिवालय
प्रेस एवं जन सम्पर्क स्कंध
संसद भवन, नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
Press and Public Relations Wing
Parliament House, New Delhi

प्रेस विज्ञप्ति PRESS RELEASE

आज राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 7वें सम्मेलन का समापन हुआ ।

.....

' वधानमंडल न केवल व ध निर्माण का कार्य कर रहे हैं, अ पतु आ र्थक और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में भी अग्रणी हैं' : श्रीमती आनंदीबेन पटेल

.....

' वधानमंडलों को कार्यपा लका की वत्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लए एक सजग प्रहरी की तरह कार्य करना चाहिए': लोक सभा अध्यक्ष

.....

लखनऊ, **17** जनवरी **2020:** 'जन प्रतिनि धयों की भू मका ' वषय पर 16 जनवरी 2020 को आरंभ हुए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के दो दिवसीय 7वें सम्मेलन का आज समापन हुआ। सम्मेलन में भारत केंद्र शाखा (भारत की संसद) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शाखाओं से 35 डे लगेट्स ने भाग लया। साथ ही, Australia और South East Asia सी पी ए रीजन के प्रतिनि धयो ने भी हिस्सा लया। इसके अलावा, इन दो दिनों के सम्मेलन में, मंत्रिगण और उत्तर प्रदेश वधान सभा और उत्तर प्रदेश वधान परिषद के लगभग270 वधायक उपस्थित रहे।

आज समापन सत्र में प्रतिनि धयों को संबो धत करते हुए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा क वगत वर्षों के दौरान वधानमंडलों के कार्य के स्वरूप में बदलाव हुए हैं। उनके यह भी वचार थे क आज के समय वधानमंडल न केवल व ध निर्माण का कार्य कर रहे हैं, अ पतु आ र्थक और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में भी अग्रणी हैं। इसके परिणामस्वरूप, वधायी निकायों के सदस्यों के रूप में जन प्रतिनि धयों की भू मका भी बदल गई हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया क सभा के भीतर और बाहर जन प्रतिनि धयों द्वारा कए जाने वाले कार्यों के आधार पर उनका मूल्यांकन कया जाता है। अतः उनसे सामाजिक समस्याओं को समझने और वधानमंडलों तथा संसद के माध्यम से उनके समाधान में प्रमुख भू मका निभाए जाने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने यह भी कहा क जन प्रतिनि धयों के रूप में यह आवश्यक है क वे संसदीय परंपराओंनियमों और प्र क्रयाओं का इस प्रकार प्रयोग करें जिससे वकासात्मक कार्य और जन कल्याण सुनिश्चित हो सके।

सम्मेलन में हुई परिचर्चाओं में स क्रय एवं सार्थक रूप से भाग लेने के लए प्रतिनि धयों को धन्यवाद देते हुए, लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने अपने समापन भाषण में कहा क इस प्रकार वचारों और अनुभवों को साझा कए जाने से वधानमंडलों के समक्ष आ रही चुनौतियों से निपटकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद

मलती है। श्री बिरला ने इस बात पर जोर दिया क वधायी संस्थाएं आम लोगों के सरोकारों, उनकी आशाओं और और आकांक्षाओं को मुखरित कए जाने के वश्वसनीय मंच होते हैं, जिन्हें सभा में जन प्रतिनि धयों द्वारा प्रभावी ढंग ढंग से उठाया जाना चाहिए।

सम्मेलन के पहले पूर्ण सत्र अर्थात् 'बजट प्रस्तावों की संवीक्षा के लए जन प्रतिनि धयों की क्षमता बढ़ाना' का उल्लेख करते हुए, श्री बिरला ने कहा क वधानमंडलों को कार्यपा लका की वत्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लए एक सजग प्रहरी की तरह कार्य करना चाहिए। इसके लए , यह आवश्यक है क जन प्रतिनि धयों को वत्तीय शब्दावली और बजटीय प्र क्रयाओं की बेहतर समझ हो। उन्होंने बजटीय प्र क्रया की बारी कयों को समझने के लए जनप्रतिनि धयों की क्षमता को बढ़ाने के लए अनुभवी सांसदों और पदा धकारियों की टीम को भेजने का प्रस्ताव रखा। 'जन प्रतिनि धयों का ध्यान वधायी कार्यों की ओर बढ़ानासंबंधी दूसरे पूर्ण सत्र के बारे में, श्री बिरला ने कहा क जनप्रतिनि धयों को उपलब्ध सभी प्र क्रयात्मक साधनों का प्रभावी रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया क राज्य वधानमंडलों को सत्रों के दौरान लोक सभा द्वारा आरंभ कए गए पैटर्न के अनुसार वधायी कार्य संबंधी सं क्षप्त जानकारी सत्र आयोजित करने पर भी वचार करना चाहिए । श्री बिरला ने कहा क प्रतिनि धगण इस बात पर एकमत हैं क वधानमंडलों को व्यवधानों के बिना सुचारू रूप से कार्य करना चाहिए । इसके लए , नियम बनाए जाएं और वधानमंडलों में नियमों में एकरूपता लाने के लए प्रयास कए जाने चाहिए । सम्मेलन में उभरी आम सहमति का जिक्र करते हुए श्री बिरला ने कहा क संसद सहित सभी वधानमंडलों की डबेट्स को एक प्लेटफार्म पर लाने का प्रयास कया जायेगा। इसके अलावा इस बात पर भी आम सहमति थी की ऐसे सम्मेलन ग्राम पंचायत, नगरपा लका अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष , युवाओं और महिलाओं के स्तर पर भी आयोजित कये जाएं।

डेलीगेट्स को धन्यवाद् देते हुए उत्तर प्रदेश वधान सभा के अध्यक्ष , श्री हृदय नारायण दी क्षत ने कहा क बदलती परिस्थिति में वधायकों का काम बढ़ा है और साथ ही उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। उन्होंने कहा अपने कार्य को सम्पादित करने के लए वधायकों को को यह समझना आवश्यक है क ज्ञान और अनुभव का इसमें अत्यंत महत्व है। ले कन केवल सं वधान और सदन की नियमावली पढ़कर सफल नहीं हुआ जा सकता। सफलता के लए यह आवश्यक है क वधायक सदन की कार्यवाही में निय मत रूप से भाग लें और गरिमामयी भाषा में अपने वचार सदन में रखें। उन्होंने जोर देकर कहा क वधायक सदन को आदर और श्रद्धेय भाव से देखें।

उत्तर प्रदेश वधान परिषद के सभापति, श्री रमेश यादव ने भी समापन समारोह में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत कया ।

आज, 17 जनवरी, 2020 को सम्मेलन में दूसरे पूर्ण सत्र के वषय अर्थात् "जनप्रतिनि धयों का ध्यान वधायी वधायी कार्यों की ओर बढ़ाना" पर चर्चा की गई । अल्पसंख्यक कार्य मंत्री , श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने मुख्य भाषण में कहा क वधायकों का मुख्य कार्य कानून बनाना है और इस लए उन्हें नीतिगत मुद्दे की पहचान करने के साथ ही उस मुद्दे का समाधान करने के लए संभा वत वधायी वकल्पों का चयन करने तथा संबं धत हितधारकों के साथ परामर्श करने में सक्षम होना चाहिए । कार्यपा लका की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी

वधानमंडलों का एक महत्वपूर्ण कार्य है । इन वधायी जिम्मेदारियों को निभाने के लए यह आवश्यक है क वधायकों को क्षेत्र वशेष से संबं धत शोध सहायता उपलब्ध हो । इस दिशा में, उन्होंने इस बात की प्रशंसा की क वधायी कार्य को संसद में प्रस्तुत कए जाने से पहले उसके संबंध में सं क्षप्त जानकारी प्रदान करने की सु वधा आरंभ की गई है ।दूसरे पूर्ण सत्र के दौरान कई प्रतिनि धयों ने अपने वचार व्यक्त कए ।

स्मरण होगा क लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने 16 जनवरी 2020 को इस सम्मेलन का उद्घाटन कया था । मध्यप्रदेश के राज्यपाल, श्री लाल जी टंडन; उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ; उत्तर प्रदेश वधान सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री हृदय नारायण दी क्षत, उत्तर प्रदेश वधान परिषद के माननीय सभापति, श्री रमेश यादव और उत्तर प्रदेश वधान सभा में नेता प्रतिपक्ष , श्री राम गो वंद चौधरी ने कल उद्घाटन समारोह के दौरान कल गण्यमाण्य व शष्टजनों की इस सभा को संबो धत कया था ।

16 जनवरी 2020 को ही सम्मेलन के पहले पूर्ण सत्र के वषय अर्थात 'बजट प्रस्तावों की संवीक्षा के लए जन प्रतिनि धयों की क्षमता बढ़ाना' पर चर्चा की गई थी । मुख्य भाषण देते हुए राज्य सभा के उप सभापति , श्री हरिवंश ने कहा क सभी जन प्रतिनि धयों की साझी आकांक्षा है क भारत आ र्थक महाशक्ति बने। इसके लए यह ज़रूरी है क व धनिर्माताओं के पास बजट की संवीक्षा करने के लए पर्याप्त कौशल और जानकारी हो । उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया क व धनिर्माताओं के लए ज़रूरी है क सामाजिक और आ र्थक संकेतकों को समझने के लए उन्हें तकनीकी शब्दावली और तकनीकों की जानकारी हो । इस संबंध में , उन्होंने वत्तीय नियमों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों और बजट के अन्य तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी देने में तकनीकी वशेषज्ञों की भू मका के महत्व का उल्लेख भी कया। अनेक पीठासीन अ धकारियों ने इस वषय पर अपने वचार व्यक्त कए ।

16 जनवरी, 2020 को लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने 'उत्तर प्रदेश वधान सभा: ऐतिहा सक पृष्ठभू म नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन कया जिसमें 1922 से उत्तर प्रदेश वधान सभा के वकास की यात्रा दर्शाई गई थी । यह प्रदर्शनी उत्तर प्रदेश वधान भवन के फॉयर में लगाई गई थी ।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की 180 शाखाएं हैं जो राष्ट्रमंडल के उन सदस्य देशों के वधानमंडलों में बनाई गई हैं जहां संसदीय लोकतंत्र है । राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की सभी शाखाओं का वर्गीकरण नौ भौगो लक राष्ट्रमंडल क्षेत्रों में कया गया है ।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र , जो पहले सीपीए ए शया क्षेत्र का भाग था , 7 सतम्बर, 2004 से स्वतंत्र क्षेत्र बन गया । सीपीए भारत क्षेत्र में भारतीय संघ शाखा(भारत की संसद) और 36 राज्यों/संघ शा सत क्षेत्रों की शाखाएँ शा मल हैं । सीपीए भारत क्षेत्र के ऐसे सम्मेलन दो वर्षों में एक बार आयोजित कए जाते हैं और छठा सम्मेलन 2018 में पटना में आयोजित कया गया था ।

THE 7TH CPA INDIA REGION CONFERENCE CONCLUDES TODAY

...

'LEGISLATURE IS NOT ONLY DOING THE WORK OF LAW MAKING, BUT IS ALSO AT THE FOREFRONT OF THE ECONOMIC AND SOCIAL CHANGE': SMT. ANANDIBEN PATEL

...

'LEGISLATURE SHOULD ACT AS A WATCHDOG ON THE FINANCIAL ACCOUNTABILITY OF THE EXECUTIVE': LOK SABHA SPEAKER

...

Lucknow, 17 January 2020: The two-day 7th CPA India Region Conference on the theme 'Role of Legislators', which commenced in Lucknow on 16 January 2020, concluded today. 35 Delegates from various branches of CPA India Region and also from Australia and South East Asia Regions participated in the event. Besides several Ministers, as many as 270 Members of Uttar Pradesh Vidhan Sabha and Uttar Pradesh Vidhan Parishad attended the two-day Conference.

Addressing the Delegates at Valedictory function today, the Governor of Uttar Pradesh, Smt. Anandiben Patel, observed that nature of the Legislatures has changed over the years. She was of the opinion that today, the Legislature is not only doing the work of law-making, but is also at the forefront of the economic and social change. As such, the role of people's representatives as members of the legislative bodies has also changed. She emphasized that the legislators are judged on the basis of their works and actions in and outside the House. They are thus expected to understand social problems and play a leading role in their redressal through Legislatures and Parliament. As the people's representatives it is necessary that they use parliamentary traditions, rules and procedures in such a way that the development work and the welfare of the public is ensured, she added.

Thanking the Delegates for their lively and meaningful participation in the deliberations of the Conference, Lok Sabha Speaker Shri Om Birla, in his Valedictory Address, said that such exchange of ideas and experiences helps in consolidating and strengthening democracy by overcoming challenges faced by legislators. Shri Birla underlined that legislative institutions are credible platforms for highlighting the concerns, hopes and aspirations of the common people, which should be effectively voiced by their representatives on the floor of the House.

Referring to the First Plenary of the Conference viz 'Capacity Building of Legislators for scrutinizing Budgetary Proposals', Shri Birla said that the Legislatures should act as a watchdog on the financial accountability of the Executive. For this, it is necessary that they have a better understanding of financial terminology and budgetary processes. He offered to send teams of experienced parliamentarians and officials for capacity building of legislators to understand the intricacies of the budgetary process. As regards the Second Plenary on 'Enhancing Focus of Legislators on Legislative Business', Shri Birla observed that legislators should use all available procedural devices effectively. He suggested that State Legislatures should also consider conducting Briefing Sessions on legislative business during the Sessions on the pattern introduced by Lok Sabha. Shri Birla mentioned that the Delegates were of the unanimous view that the Legislatures should work smoothly without disruptions. For this, rules may be framed and efforts should be made for bringing about uniformity in the rules across the Legislatures. Referring to decisions taken at the Conferences, Shri Birla said that debates of all Legislatures, including the Parliament, would be brought at a single platform. Besides, there was a unanimity that such conferences at the level of Gram Panchayat, Nagarpalika, Districts are also organised.

Thanking the delegates, Speaker, Uttar Pradesh Vidhan Sabha, Shri Hriday Narayan Dikshit, observed that the mandate of Legislators has increased with the changing times. He said that they should understand that knowledge and experience are important for performing their work. He, however,

cautioned them that mere reading of the Constitution or the rules of procedure is not enough. It is important that Legislators participate in the proceedings of the House regularly and articulate their views in a dignified manner. He emphasized that Legislators should should look at the House with a sense of respect and dedication.

Chairman, Uttar Pradesh Vidhan Parishad Shri Ramesh Yadav gave Vote of Thanks.

Earlier today, 17 January 2020, the Conference took up the discussion on the second Plenary item, viz. 'Enhancing Focus of Legislators on Legislative Business'. Delivering the keynote address, Union Minister of Minority Affairs, Shri Mukhtar Abbas Naqvi said that the legislators are primarily required to engage in law-making and therefore they must be able to identify a policy issue, potential legislative options to address that issue and consult relevant stakeholders. Ensuring the accountability of the Executive is also one of the core functions of the Legislature. To perform these legislative responsibilities, it is imperative that legislators have access to sector-specific research support. In this direction, he lauded the introduction of Briefing Sessions on legislative business before the Parliament. Several Delegates shared their views during the second plenary.

It may be recalled that Lok Sabha Speaker Shri Om Birla had inaugurated the Conference on 16 January 2020. Governor, Madhya Pradesh Shri Lal ji Tandon; Chief Minister of Uttar Pradesh Shri Yogi Adityanath; Speaker, Uttar Pradesh Vidhan Sabha, Shri Hriday Narayan Dikshit; Chairman, Uttar Pradesh Vidhan Parishad, Shri Ramesh Yadav; and Leader of Opposition, Uttar Pradesh Vidhan Sabha, Shri Ram Govind Chaudhary addressed the distinguished gathering during the Inaugural Function yesterday.

Later in the day on 16 January 2020, the Conference held discussions on its first Plenary item, viz. 'Capacity Building of Legislators for scrutinizing Budgetary Proposals'. Delivering the keynote address, Deputy Chairman, Rajya Sabha Shri Harivansh observed that it is the common aspirations of all representatives to make India an economic superpower. For this, it is necessary that lawmakers have adequate skills and knowhow to scrutinize the budget. He emphasized that it is incumbent upon lawmakers to understand technical terminology and techniques to decipher social and economic indicators. In this regard, he highlighted the role of technical experts in explaining about the financial rules, C&AG reports and other technical aspects of the budget. Many Presiding officers shared their views on the subject.

On 16 January 2020, Lok Sabha Speaker Shri Om Birla inaugurated an exhibition titled "Uttar Pradesh Vidhan Sabha: Historical Background", depicting the journey of evolution of U.P. Legislative since 1922. The exhibition was set up in the foyer of the Uttar Pradesh Vidhan Bhawan.

The Commonwealth Parliamentary Association (CPA) is composed of over 180 Branches formed in Legislatures of Commonwealth countries enjoying parliamentary democracy. All the CPA Branches are geographically grouped into nine Commonwealth Regions.

The CPA India Region, which was earlier a part of CPA Asia Region, became an independent Region from 7 September, 2004. The India Region of CPA consists of the India Union Branch (Parliament of India) and 36 States / Union Territories Branches. Such Conferences of CPA India Region are held once in two years and the 6th Conference was held in 2018 in Patna.